

प्रथम कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय AI संधि

प्रलिमिस के लिये:

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), यूरोपीय संघ, जैव विविधता पर अभसिमय

मेन्स के लिये:

यूरोप के AI अभसिमय के संदर्भ में मुख्य तथ्य।

सरोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

काउंसलि ऑफ यूरोप के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड कंगडम और यूरोपीय संघ के सदस्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पर प्रथम कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय AI संधिपर हस्ताक्षर करने में सक्षम होंगे।

काउंसलि ऑफ यूरोप (COE)

- काउंसलि ऑफ यूरोप (COE) एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में स्थिति है।
- यह यूरोपीय संघ (EU) से अलग है और इसमें अधिकांश यूरोपीय देशों सहित 46 सदस्य देश शामिल हैं।
- COE का प्राथमिक मशिन अपने सदस्य देशों में लोकतान्त्र, मानवाधिकारों और विधिके शासन को बनाए रखना तथा उसे बढ़ावा देना है।

AI अभसिमय के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- परचिय:**
 - "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानवाधिकार, लोकतान्त्र एवं कानून के शासन पर फ्रेमवर्क अभसिमय (The Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy, and the Rule of Law)", मुख्य रूप से AI प्रणालियों से प्रभावित व्यक्तियों के मानवाधिकारों के संरक्षण पर ज़ोर देता है तथा यूरोपीय संघ के AI अधनियम से स्वतंत्र रूप से संचालित होता है।
 - यूरोपीय संघ AI अधनियम यूरोपीय संघ के आंतरिक बाजार में AI प्रणालियों के विकास, परनियोजन और उपयोग को नियंत्रित करने वाले व्यापक नियम स्थापित करता है।
 - AI अभसिमय पर कई वर्षों से कार्य चल रहा था और इसे 57 देशों के बीच विचार-विमर्श के बाद मई 2024 में अपनाया गया।
 - इसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखियों को कम करना है।
- संधिकी शर्तें:**
 - मानव-कैंदरति AI:** संधिमें यह अनविार्य किया गया है कि AI प्रणालियों को मानवाधिकार संदर्भातों के अनुरूप विकसित और संचालित किया जाना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे लोकतान्त्रिक मूल्यों का समर्थन एवं संरक्षण करते हैं।
 - पारदर्शिता और जवाबदेही:** इस संधिमें प्रावधान है कि AI प्रणालियों, विशेषकर मनुष्यों के साथ अंतःक्रिया करने वाली प्रणालियों को पारदर्शी रूप से संचालित किया जाना चाहिये।
 - इसमें सरकारों से यह भी अपेक्षा की गई है कि वे AI प्रणालियों द्वारा मानव अधिकारों का उल्लंघन किये जानेपर कानूनी उपाय उपलब्ध कराएं।
 - जोखिम प्रबंधन और नरीकरण:** यह संधि AI से जुड़े जोखियों का आकलन और प्रबंधन करने के लिये रूपरेखा स्थापित करती है, साथ ही सुरक्षा एवं नैतिक मानकों का पालन सुनिश्चित करने हेतु नरीकरण तंत्र भी स्थापित करती है।
 - दुरुपयोग के विविध संरक्षण:** संधि में न्यायिक स्वतंत्रता के संरक्षण और न्याय तक जनता की पहुँच सुनिश्चित करने सहित लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं को कमज़ोर करने हेतु AI के उपयोग को रोकने के लिये सुरक्षा उपाय शामिल किये गए हैं।

■ प्रमुख प्रवरतन तंत्र:

- कानूनी जवाबदेही: हस्ताक्षरकरता देशों को यह सुनिश्चित करने के लिये विधायी और प्रशासनिक उपाय करने की आवश्यकता है कि AI प्रणालियाँ संधिके संदर्भात्मा जैसे मानव अधिकारों तथा AI परनियोजन में जवाबदेही का पालन करें।
- नगिरानी और नरीकृष्ण: संधिएँ AI मानकों के अनुपालन की नगिरानी के लिये नरीकृष्ण तंत्र स्थापित करती है।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: यह संधिएँ AI मानकों में सामंजस्य स्थापित करने, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और AI प्रौद्योगिकियों की वैश्वकि प्रकृतिको मान्यता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय AI मुद्दों को हल करने के लिये हस्ताक्षरकरताओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देती है।
- अनुकूलनशीलता: इस ढाँचे को प्रौद्योगिकी-तटस्थ रहने हेतु वकिसति कथिा गया है, जिससे यह AI में प्रगतिके साथ-साथ वकिसति हो सके तथा यह सुनिश्चित हो सके कि AI प्रौद्योगिकियों की तीव्र प्रगतिके बावजूद मानक प्रासंगिक और लागू करने योग्य बने रहें।
- संधिमें अपवाद: यह संधिराष्ट्रीय सुरक्षा या रक्षा में प्रयुक्त होने वाली प्रणालियों को छोड़कर सभी AI प्रणालियों पर लागू होती है, हालाँकि इसमें अभी भी यह अपेक्षा की गई है कि ये गतिविधियाँ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और लोकतांत्रिक संविधानों का सम्मान करें।



कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)

AI मरीनों में मानव बुद्धि का अनुकरण है, जिसे मनुष्यों की तरह सोचने और सीखने के लिये प्रोग्राम किया गया है, जो समस्या-समाधान, तर्क और नई जानकारी के अनुकूल होने में सक्षम है।

AI टाइमलाइन - प्रमुख परिवर्तन (Milestones)

- 1950s का दशक: ट्यूरिंग टेस्ट का प्रस्ताव; पहला AI प्रोग्राम विकसित
- 1956 डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस ने "कृत्रिम बुद्धिमत्ता" को मान्यता दी
- 1960s का दशक: एलिजा चैटबॉट का निर्माण; प्रारंभिक न्यूरल नेटवर्क
- 1996 डीप ब्लू - एक शतरंज खेलने वाला प्रोग्राम (Chess-Playing Program)
- 2012 डीप लर्निंग ब्रेक थू इन इमेज रिकॉग्निशन
- 2014 जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क (GAN) का प्रस्ताव
- 2020 GPT-3 द्वारा उन्नत भाषा निर्माण का प्रदर्शन
- 2022 चैटजीपीटी लॉन्च हुआ, जो संवादात्मक AI को आम लोगों तक पहुँचाएगा
- 2023 जनरेटिव AI बूम; प्रमुख टेक कंपनियों ने AI मॉडल जोरी किये



AI के अनुप्रयोग

- स्वास्थ्य सेवा: व्यक्तिगत चिकित्सा
- वित्त: एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग
- परिवहन: ऑटोनोमस व्हीकल
- विपणन और ग्राहक सेवा: टार्गेट एडवरटाइजिंग चैटबॉट
- शिक्षा: अडेप्टिव लर्निंग सिस्टम
- कृषि: फसल निगरानी
- साइबर सुरक्षा: खतरे का पता लगाना
- ऊर्जा: स्मार्ट ग्रिड प्रबंधन, खपत पूर्वानुमान

चिंताएँ

- डीपफेक और गलत सूचना
- एल्गोरिदमिक बायस
- ऑटोमेशन और जॉब डिस्प्लेसमेंट
- गोपनीयता के मुद्दे
- डेटा ऑनरशिप और लायबिलिटी इश्यु
- एथिकल डिसीजन-मेकिंग कॉम्प्लेक्स

AI विनियमन

- AI पर वैश्विक भागीदारी (GPAI) 2020 में प्रारंभ हुई
- ब्लेचली घोषणा (2023): AI पर वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना
- G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लरेशन (2023):
- AI पर G7 हिरोशिमा (2023) प्रोसेस

भारत और AI

- AI 2021 के लिये राष्ट्रीय रणनीति
- AI फॉर ऑल: स्व-शिक्षण ऑनलाइन कार्यक्रम
- भारत द्वारा आयोजित GPAI शिखर सम्मेलन 2023
- इंडिया AI मिशन 2024
- US इंडिया अर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (USIAI) पहल: महत्वपूर्ण क्षेत्रों में AI सहयोग
- AIRAWAT (AI रिसर्च एनालिटिक्स और नॉलेज सेपरिफ्यूजन प्लेटफॉर्म) सुपरकंप्यूटर

प्रमुख AI प्रौद्योगिकियाँ



- व्यापक प्रारूपण:** संधि का मसौदा सावधानीपूर्खक तैयार किया गया था, जिसमें AI प्रणालियों के संरचना, विकास, उपयोग और डीकमीशनिंग (decommissioning) के लिए जोखमि-आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया था।
- व्यापक प्रयोज्यता:** यह विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में प्रवर्तन के साथ सार्वजनिक क्षेत्र और नजीकी क्षेत्र दोनों में AI प्रणालियों पर लागू होता है।
- वैश्वकि कानूनी मानक:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर फ्रेमवर्क अभियान अपनी तरह की पहली वैश्वकि रूप से बाध्यकारी संधि है, जिसे साझा मूल्यों वाले विभिन्न महादीपों के देशों द्वारा समर्थित अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मानक की आवश्यकता को पूरा करने हेतु तैयार किया गया है।
- नवाचार और जोखमि में संतुलन:** संधि का उद्देश्य AI के लाभों का दोहन करते हुए इसके अनुकूल उपयोग को बढ़ावा देना है, साथ ही इससे जुड़े जोखमियों को प्रभावी ढंग से कम करना है तथा यह सुनिश्चित करना है कि AI का विकास मानव अधिकारों, विधि के शासन और लोकतांत्रिक संविधानों के अनुरूप हो।

AI अभियान के मुद्दे और चित्ताएँ क्या हैं?

- प्रवर्तन पर चित्ताएँ:** "कानूनी रूप से बाध्यकारी" घोषित कर दिये जाने के बावजूद, इस संधि निवेदितमक प्रतिबिधियों, जैसे किंजुरमाना या दंड के प्रभावानों की कमी के कारण चित्ताएँ उत्पन्न की हैं, जो प्रवर्तन के दृष्टिकोण से इसके निवारक प्रभाव को कमज़ोर करता है।
- नगिरानी पर नियमिता:** संधि का अनुपालन मुख्य रूप से "नगिरानी" तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है, जो संधि के प्रभावानों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु प्रयोग्य नहीं हो सकता है।
- विनियमन और नवाचार को संतुलित करना:** कड़े विनियमन और नवाचार को बढ़ावा देने के बीच सही संतुलन बनाना एक महत्वपूर्ण चित्ता का विषय है। अत्यधिक विनियमक बोझ AI प्रौद्योगिकियों के विकास को बाधित कर सकता है, विशेष रूप से लघु एवं मध्यम उद्यमों (SME) और स्टार्टअप के लिये, जिससे वैश्वकि AI बाज़ार में प्रतिसिप्रदातामकता प्रभावित हो सकती है।
- राष्ट्रीय संप्रभुता बनाम अंतर्राष्ट्रीय मानक:** संधि के प्रभावान राष्ट्रीय कानूनों के साथ टकराव उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे राज्य संप्रभुता के बीच तनाव उत्पन्न हो सकता है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा चित्ताओं का समाधान:** सम्मेलन राष्ट्रीय सुरक्षा हतियों के साथ AI शासन को संतुलित करने का प्रयास करता है, जबकि रिक्षा और खुफिया गतिविधियों के साथ AI का प्रतिक्षेपन चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है। यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा रहा है, जबकि नैतिक AI प्रथाओं को बनाए रखने के लिये एक संतुलन अधिनियम की आवश्यकता है, जिसे हासिल करने के लिये इस संधि को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

निषिकरण

"आरटिफिशियल इंटेलिजेंस और मानवाधिकार, लोकतंत्र तथा कानून के शासन पर फ्रेमवर्क अभियान" आरटिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्वकि शासन में एक महत्वपूर्ण प्रगति को चिह्नित करता है। AI, मानवाधिकार, लोकतंत्र और विधि के शासन के बीच महत्वपूर्ण अंतरसंबंधों को शामिल करके, यह वर्तमान नियमक संरचनाओं में एक महत्वपूर्ण कमी का समाधान करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा विद्यार्थियों के प्रभावानों सहित इसका व्यापक दायरा ज़मिनदार AI शासन के लिये एक बेंचमार्क स्थापित करता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है एवं ऐसे मानक नियमिता करता है, जो क्षेत्रीय एवं वैश्वकि दोनों स्तरों पर प्रतिधिवनति हो सकते हैं।

दृष्टिमुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: ग्लोबल आरटिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस शासन के संदर्भ में यूरोप के AI अभियान से जुड़े प्रमुख मुद्दों और चित्ताओं पर चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विभिन्न वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. विकास की वर्तमान स्थितिके साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता नियन्त्रिति में से क्या प्रभावी ढंग से कर सकता है? (2020)

१. औद्योगिक इकाइयों में बजिली की खपत को कम करना
२. सारथक लघु कथाएँ और गीत की रचना
३. रोग नियन्त्रिति
४. टेक्स्ट-टू-संपीच रूपांतरण
५. विद्युत ऊर्जा का वायरलेस संचरण

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1, 2, 3 और 5
 (b) केवल 1, 3 और 4
 (c) केवल 2, 4 और 5
 (d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (b)

